*नेशनल काउन्सिल फोर बिल्डिंग ए बेटर फीजी*

# सलाह-मश्विरा वाला कागज़ात

# देश की स्थिति तथा अर्थव्यवस्था रिपोर्ट

## की तैयारी के लिए

तकनीकी और सहयोगी सेक्रेटेरियट
संसदीय भवन
पी.ओ. बोक्स 2645
गर्व्मंट बिल्डिंग्स
ई मेल करें: tass@govnet.gov.fj

# विषय प्रवेश

यह कागज़ात देश तथा अर्थ व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहा है, साथ ही इसमें फीजी की जटिल तथा गहरी समस्याओं पर भी कुछ प्रकाश डाला गया है। इसमें उन विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है जिनपर ध्यान देना ज़रूरी है ताकि फीजी को एक बेहतर देश बनाया जा सके।

इस कागज़ात में जो जानकारी तथा प्रारम्भिक मूल्यांकन होंगे, उससे राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की स्थिति पर एस एन ई रिपोर्ट के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में जनता को छानबीन तथा विचार-विमर्श करने के विस्तृत मौके मिलेंगे।

ऐसी आशा तथा अनुमान है कि राष्ट्रीय तौर पर जब भी इस सलाह-मश्विरा वाले प्रस्तावित कागज़ात पर विचार-विमर्श होंगे, उसमें देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विचार भी प्राप्त होगा जो फिलहाल जारी है। जनता अपने विचार तथा ख़ासकर उन विषयों को इसमें शामिल कर सकेंगी जो वे सोचते हैं कि इस कागज़ात में शामिल नहीं किया गया है।

यह एक सलाह-मश्विरा वाला कागज़ात ही है। इसका मतलब यह है कि इसमें जो आंकड़े या तथ्य शामिल हैं, वे सही हैं जिसके आधार पर तकनीकी सेक्रेटेरियट (टी ए एस एस) राष्ट्रीय सलाह-मश्विरा प्रक्रिया के दौरान विभिन्न भागीदारों तथा साझेदारों से उनके प्रारम्भिक और अस्थाई विचार प्राप्त करेगा। यह प्रक्रिया या तो पुष्टि करेगी या फिर इस कागज़ात में प्रस्तुत विचारों का प्रारम्भिक मूल्यांकन या फिर रद्दोबदल करेगी। इस सलाह-मश्विरा की प्रक्रिया का यह मतलब नहीं होगा कि किसी एक के लक्ष्य को थोपा जाएगा, लेकिन इसका मतलब यही होगा कि फीजी के समक्ष जो समस्याएं हैं, उनपर व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर गहरी तथा विस्तृत समझबूझ प्राप्त होगी जो इन समस्याओं को सुलझाने की आवश्यक सीढ़ी होगी।

जो गैर-सरकारी संस्थाएं, समूदायिक दल, प्रायवट सेक्टर कम्पनियां या व्यक्ति इस कागज़ात में नीहित जानकारियों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या फिर प्रतिकियाएं देना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और ऐसा वे सेक्रेटेरियट के पास लिखकर कर सकते हैः

## एस एन ई रिपोर्ट टीम

तकनीकी और सहयोगी सेक्रेटेरियट
संसदीय भवन
पी.ओ. बोक्स 2645
गर्वमंट बिल्डिंग्स
ई मेल करेंः tass@govnet.gov.fj

# देश और अर्थ व्यवस्था की हालात
## सलाह-मश्विरा वाला कागज़ात

### आरम्भ

फीजी 10 अक्टूबर 1970 को आज़ाद हुआ। उस दिन के बाद से देश के सभी लोगों में भारी आशाएं जागी कि एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए मार्ग तय किया जाए जहां शान्ति, सहनशीलता, सांस्कृतिक मेलजोल तथा हर एक नागरिक के लिए समृद्धिशील भविष्य हो; एक ऐसा देश जो सिर्फ अन्तरराष्ट्रीय परिवारिक देशों में भागीदारी ही न बने, बल्कि यह दर्शाए कि "इसी तरह ही विश्व को होना चाहिए"।

आज, सैंतीस वर्ष बाद ये कई आशाएं टूट गई हैं। देश के लोग अब भारी संख्या में चिन्तित तथा असन्तुष्ट हैं। एक सहनशील, एकता वाले देश तथा समृद्धिशील राष्ट्र के लिए जो सपना था, वो एक अलग वास्तविकता की जगह ले ली है: राजनीतिक अस्थिरता, एक के बाद एक होने वाला सत्ता पलटाव, अस्थिर अर्थ व्यवस्था, धार्मिक तथा जातिए असहनशीलता का बढ़ावा, अपराध और हिन्सात्मक घटनाओं में वृद्धि, बढ़ रही गरीबी, अनुभवी तथा हुनर वाले लोगों का देश छोड़ना और कई लोगों में आशाएं और उम्मीद टूटना ही ऐसी वास्तविकता से जुड़ी है।

क्या गलत हुआ है?

आमतौर पर यह स्पष्ट है कि काफी कुछ सही नहीं हुआ है। इसलिए अब यह समय आ गया है कि हम रूक कर सोचे, पुनःगौर करें कि फीजी किस दिशा में जा रहा है। अब यह समय है कि नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया जाए: एक परिवार की तरह, एक राष्ट्र की तरह, एक ही भविष्य की ओर।

सलाह-मश्विरा वाला कागज़ात ये देखता है:

i) देश की वर्तमान स्थिति;

ii) फीजी द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के कारण; और

iii) उन विषयों और समस्याओं को जिनपर फीजी के सभी लोगों को स्पष्ट रूप से तथा गम्भीरतापूर्वक ध्यान देने की तथा ज़ोर देने की ज़रूरत है ताकि सभी के लिए बेहतर फीजी का निर्माणकार्य शुरू हो सके।

## भाग १

# देश की वर्तमान स्थिति

फीजी में 1970 में स्वतंत्रता के बाद से मुख्य समस्या गत कुछ वर्षों में उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता तथा बिगड़ रहा शासन रही है। 1987 में प्रथम सत्ता पलटाव होने के बाद, अन्तरराष्ट्रीय समाज में आज देश के बारे में यह छवि है कि यहां 'सत्ता पलटाव की संस्कृति' है। फीजी को ऐसा देश माना गया है जहां वर्तमान सरकार से नाखुश एक दल गैर-संवैधानिक कार्यवाहियां कर रहा है।

ऐसी हालात में, जहां संविधान को कोई मान्यता नहीं देता है, उससे संविधान की विश्वसनीयता और वैधता बुरी तरह कमज़ोर होता है। इस स्थिति की एक वजह यह है कि कुछ ही लोग संविधान के मुख्य सिद्धांतों को समझते हैं।

**फीजी के संविधान के मुख्य सिद्धांत**

फीजी के संविधान ने सरकारी प्रणाली और मानवाधिकारों की सुरक्षा का आम ढांचा उपलब्ध किया है। फीजी का संविधान परिणामों में समानता को नहीं देखता, बल्कि उसने उपलब्धियों में समानता को मुख्य मानवाधिकार माना है। विशेष रूप से उसका लक्ष्य है:

- लोगों को शांति और एकता में रखना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना तथा सभी समाजों को आर्थिक और सामाजिक बढ़ावा देना, उसके अधिकारों और रुचियों का सम्मान करना तथा सरकारी संस्थाओं को मज़बूती प्रदान करना; और
- परिवारों के महत्व के लिए मानव आत्मसम्मान तथा कानून को साथ लेकर दलों की मुख्य स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को पुनःमान्यता देने की पुष्टि करना।

उपरोक्त सिद्धांतों से राष्ट्रीय संसाधनों में मज़बूती, राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का नियन्त्रण, आर्थिक रूप से स्वयं निर्भरता तथा असरकारिता लाने की आशा की जाएगी। यह निर्भरता इस कदर प्राप्त होगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा देखरेख की सुरक्षा, स्वतंत्रता तथा प्रत्येक नागरिक को सामाजिक न्याय, समानता और बराबर मौकों के आधार पर खुशियां मिल सकेगी।

फीजी के संविधान ने अपनी कुछ विश्वसनीयता खो दी है। इसका कारण अधिकांश हिस्सा जातिए भेदभाव पैदा करने वाला ढांचा और स्वयं चुनाव प्रणाली है। फीजी ने कम से कम तीन मर्तबा प्रजातांत्रिक सरकारी प्रणाली को कायम रखने में असफलता प्राप्त की है जोकि इस देश के कानून और संविधान के परे है। कई कारणों से देश प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र कायम नहीं कर सका। इसका कारण फीजी का वर्तमान चुनाव प्रणाली है। चुनाव प्रणाली के मार्फत समुदायों के बीच भिन्नताएं सुलझाने की जो कोशिश की गई थी, उसके कारण फीजी की मतदान प्रणाली में रद्दोबदल हुआ। हालांकि अलग सम्प्रदायिक चुनावक्षेत्र और मतदान सूची को एक सदस्य वाली चुनाव प्रणाली के तहत कायम रखा गया। 1997 संविधान के तहत ओल्टेनेटिव़ व़ोट सिस्टम के नीचे तीन आम चुनाव हुए जिनसे सम्प्रदायिक भिन्नताएं और ज़्यादा बढ़ीं।

नेटिव़ ज़मीनों की लीसों को लेकर संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, उन्हें लेकर चल रही राजनीतिक विवाद हालांकि सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा सुलझाई नहीं जा सकी है, तो अब यह विषय एक मुख्य राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। इसके कारण कई लीसों का नवीनीकरण नहीं हुआ और कई असामियों को अपना घर छोड़ कर झोपड़पट्टियों में रहना पड़ रहा है। ये बेघर हुए लोग नौकरी खोजने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। पूर्व में लीस की गई ज़मीन अब परती पड़ी हुई हैं। इसका मतलब है कि लोग और गरीब हो गए हैं। इनमें न सिर्फ असामी हैं, बल्कि ज़मीनमालिक भी हैं जो अब अपनी ही ज़मीन से कुछ भी पैसा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। नेटिव़ लेण्ड ट्रस्ट बोर्ड द्वारा जिस तरह से ज़मीन मालिकों की ज़मीनों को लेकर निर्णय लिया जा रहा है, उसपर फीजियन ज़मीनमालिकों ने और ज़्यादा असन्तुष्टि व्यक्त की है। देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए ग्रेट काउन्सिल ओफ चीफ्स ने जिस तरह से बेअसरकारक ढंग से नेतागिरी सम्भाली है, उसे भी अपसंद किया गया है।

1970 के बाद से बने हुए सभी संविधानों में जेनरल, 'इंडियन' तथा फीजियन रोल्स के अलग-अलग चुनाव प्रतिनिधित्व की व्यवस्थाएं रही हैं। इसके अन्तर्गत संसदीय सदस्य जो कोम्युनल रोल्स की सीटों से चुने जाते हैं, वे अन्य समुदायों की चिन्ताओं को लेकर किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं हो सकते हैं। इन व्यवस्थाओं के कारण कुछ राजनीतिज्ञों को अपने हित के लिए समुदायिक और धार्मिक भिन्नताओं को बढ़ा-चढ़ा कर काम में लाने का मौका प्राप्त हुआ है। इनसे फीजी को एक राष्ट्र होने के नाते, सभी समुदायों के बीच विश्वास की कमी,

धार्मिक और जातिए असनशीलता में वृद्धि तथा घृणा जैसे परिणाम मिले हैं। 1987 और 2000 सत्ता पलटाव के बाद मंदिरों और मस्ज़िदों को जलाया गया, हिन्दुओं और मुस्लमानों के धार्मिक ग्रंथो को क्षति पहुंचाई गई तथा हिन्दू पुजारियों का अपमान किया गया। 2000 में सत्ता पलटाव के प्रयास में दुकानें लूटी गईं, घर जलाए गए, पशुओं को मारा गया तथा लोगों को गैरकानूनी ढंग से उनके खेतों और घरों से निकाला गया जिन सब का आधार जातिएता था। 2001 के चुनाव के बाद बहुपार्टी मंत्रीमण्डल की संवैधानिक व्यवस्थाओं के अव्यवहारिकता का पता चला।

1980 के अंत से अपराधिक गतिविधियों में वृद्धि हुई थी। भले ही हाल के वर्षों में रिपोर्ट किए अपराधों में कमी आई है, गम्भीर अपराधों में वृद्धि हुई है। यह कुछ हद तक बेरोज़गारी और गरीबी का कारण हो सकता है, खासरूप से युवा लोगों में, लेकिन यह इसकी एक वजह फीजी में ट्रान्सनेशनल अपराधिक दलों की बढ़ती गतिविधियां है। इनमें शामिल है पैसों का अवैध व्यापार, नशीले पदार्थों के उत्पादन और वितरण, गैरकानूनी रूप से देश में घुसना, जुआखोरी और वेश्यावृत्ति। कैदखानों में कैदियों की संख्या बढ़ गई है जिससे कैदखानों में संसाधनों में कमी आई है। यह अति चिन्तनीय है कि ज़्यादातर कैदी युवा फीजियन्स हैं। इस विकास की प्रतिकिया यह रही है कि लोग अपने ही घरों में छड़ी लगे हुए कमरों में कैद हैं। अपराध अब हमारे समुदायों की एक हकीकत बन चुकी है जिसके कारण लोगों में लगातार भय और डराने-धमकाने का डर बना हुआ है जिसकी वजह से हमारे जीवन में मनोरंजन की कमी आ गई है।

1987 में प्रत्येक सत्ता पलटाव के बाद भारी तादाद में लोग विदेश चले गएं। भारी संख्या में लोगों ने यह दर्शाया कि वे फीजी की वर्तमान राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं के नीचे रहने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके कारण फीजी ने अपने योग्य और हुनर प्राप्त कर्मचारियों और मैनेजरों को खो दिया है। फीजी की स्थिति अब इतनी खराब हो गई है कि यहां पर्याप्त संख्या में योग्य कर्मचारियों और मैनेजरों की कमी है जो व्यापारों को संचालित कर के उसे बढ़ाएं ताकि लोगों के लिए नौकरियां उपलब्ध हो सके।

लगातार राजनीतिक अस्थिरता, समुदायिक हिन्सा और अपराध ने देश की आर्थिक समस्याओं को बढ़ावा दिया है। देश में आर्थिक बढ़ावा देने के लिए स्थानीय और विदेशी पूंजीपति यहां स्थिरता और विश्वसनीयता चाहते हैं क्योंकि इन्हीं के ज़रिए वे पूंजी लगाने वाले निर्णय के खतरों को कम महसूस कर सकते हैं। राजनीतिक अस्थिरता पूंजीपतियों को भयभीत कर देती है और यही एक कारण है कि क्यों फीजी की आर्थिक बढ़ौत्तरी की दर इतनी कम है: इस दिशा में पर्याप्त मात्रा में मुख्य पूंजी नहीं लगाई गईं जिससे नई नौकरियां उपलब्ध हो सके जो बढ़ते हुए लोगों की नौकरी की मांग की पूर्ति कर सके, खासकर स्कूल छोड़े हुए विद्यार्थी जिन्हें काम की ज़रूरत है। एनेक्स 1 मुख्य आर्थिक और सामाजिक संकेत देता है।

सच्चाई यह है कि स्वतंत्रता के बाद से लेकर बहुत लम्बे समय से फीजी में आर्थिक बढ़ौत्तरी की दर नीचे गिरती रही है- और यह दर लगातार बढ़ रही है: 2007 में 2006 के मिलान में आर्थिक उपलब्धि 5% कम रही है। गिरती हुई आर्थिक आमदनी, नौकरी खोने वालों की संख्या में वृद्धि तथा वेतन में कटौती से इस दर में कमी देखने को मिली है। एशिया प्रशान्तिए देशों का मिलान जब फीजी से किया जाए तो यह देखा जा सकता है कि एशिया प्रशान्तिए क्षेत्र में प्रगति पे केपिटा इन्कम में तेज़ी से हो रही है जबकि फीजी में यह काफी धीमा है। इसे आप नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं।

उत्पादकता, मतलब कम संसाधनों से ज़्यादा उत्पादन इसलिए ज़रूरी है ताकि लोग अच्छी आमदनी का लाभ उठाकर आगे बढ़ सकें।

फीजी में उत्पादकता में सुधार नहीं हो रहा है। यह एक मुख्य कारण है जो यह समझाता है कि फीजी में आर्थिक क्षमता क्यों इतनी गिरी है और देश में गरीबी क्यों बढ़ रही है।

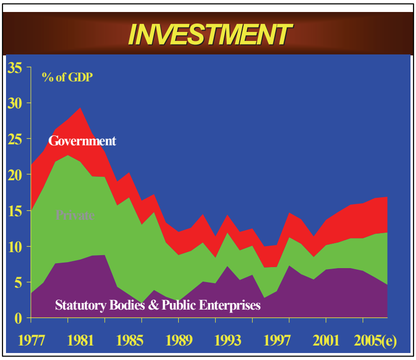


उत्पादकता को बढ़ाना आसान है अगर पूंजी लगाने की दर ऊंची हो। लेकिन हाल के वर्षों में पूंजी का स्तर 14-16 प्रतिशत जी डी पी रहा है, जो कि 1970 के वर्षों के मिलान में अवसत स्तर से बहुत ही कम रहा है। 1970 के दशक में जी डी पी स्तर 22 प्रतिशत रहा है और 1987 सत्ता पलटाव से पूर्व जी डी पी 25 प्रतिशत था।

आर्थिक संचालन को लेकर भी समस्याएं रही हैं। हाल के वर्षों में सरकार को टेक्स और अन्य आमदनी के रूप में जो पैसा मिलता रहा है, उससे कहीं ज़्यादा सरकार ने लगातार पैसा खर्च करना जारी रखा। 2001 और 2003 के बीच बजट का घाटा जी डी पी के अवसत 6.5 प्रतिशत रहा है जिसमें से ज़्यादातर सरकारी संचालन का खर्च रहा है। उधार के पैसे से बजट के घाटे की पूर्ति हुई। इससे सरकारी कर्ज़ को और बढ़ावा मिला। कर्ज़ बढ़ने के कारण सरकार को और ज़्यादा सूद कर्ज़ पर भरनी पड़ी जिसका मतलब यह है कि जिन कार्यक्रमों पर पैसा खर्च करना था, उसके लिए कम पैसा उपलब्ध हुआ और ये कार्यक्रम हैं शिक्षा और स्वास्थ्य।

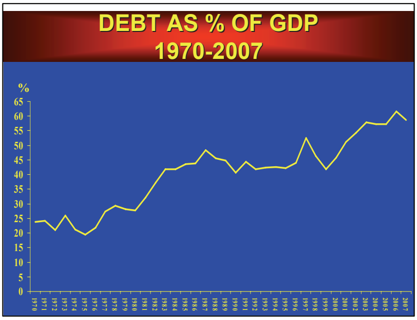


जानना आवश्यक है कि भारी घाटे वाले बजट के कारण अर्थ व्यवस्था की खपत के सम्पूर्ण स्तर पर असर पड़ा है। क्योंकि खाने वाली ज़्यादा चीज़े हम वि देश से आयात करते हैं तो वहीं आयातकर्त्ताओं को विदेशी मुद्रा में बिल्स चुकाने होते हैं। कुल विदेशी मुद्रा की जो मांग प्रति वर्ष की जाती है, वो फीजी के वार्षिक निर्यात मूल्यों से कहीं ज़्यादा है। जबकि इस भिन्नता में हाल के वर्षों में कमी आई है तो वहीं देश के पैमेंट यानी रेमिटेन्स में वृद्धि हुई है। फीजी का व्यापारिक घाटा लगातार चौड़ा हुआ है जो लगभग 2 मिलियन डोलर (जी डी पी के एक तिहाई हिस्से के आसपास) है। यही एक कारण है कि रिसर्व् बैंक ओफ फीजी ने विदेशी मुद्रा की अदला-बदली पर नियंत्रण रखना कायम रखा है। लेकिन इस विदेशी मुद्रा के एक्सचेंज पर रखे गए नियन्त्रण के कारण उन व्यापारियों को विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है जो मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स, रिस्क मैनेजमंट प्रोडक्ट (जैसे, इन्शुरन्स और फोर्वड फोरन एक्सचेंज कोन्ट्रेक्ट्स) प्राप्त करना चाहते हैं जिनसे वे अपने व्यापार को भली-भांति संचालित करते हैं। कम शब्दों में, सरकार द्वारा बनाई गई बुरी आर्थिक नीतियों से व्यापार को बढ़ावा देने और नौकरियां उपलब्ध करने में और दिक्कत हो रही है।

परिणामस्वरूप, बेरोज़गारी और नौकरी के कम मौके जैसी मुख्य समस्याएं सामने आईं। एम्प्लोयमंट एण्ड अनएम्प्लोयमंट सर्वे रिपोर्ट 2004-05 में यह अनुमान लगाया गया कि राष्ट्रीय बेरोज़गारी की दर

4.6 प्रतिशत रही। जबकि इसी रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि फीजी के मज़दूर बाज़ार में नौकरी के कम मौके 22.5 प्रतिशत है। वर्तमान में प्रति वर्ष लेबर मार्केट में 16,000 लोग नई नौकरियां ढूढ़ने के लिए निकलते हैं लेकिन सिर्फ 7,000 नई नौकरियां उपलब्ध है।

लोगों की बचत पर सूद की दर इतनी कम है कि उन्हें वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं होता और स्वतंत्रता के बाद की अवधि के दौरान यह घटता रहा है (क्योंकि सेविंग्स अकाउन्ट्स पर मिलने वाले सूद की दर के मिलान में महंगाई की दर ज़्यादा रही है)। इसी वजह से लोग बचत करने से निरूत्साहित हुए हैं और यह एक और वजह है जिसके कारण देश में बढ़ौत्तरी का संचालन स्तर नीचा है।

हाल के वर्षों में फीजी ने अमरीका में गार्मेन्ट्स को लेकर प्राथमिकता वाली व्यवस्था खो दी है और यूरोपियन यूनियन में चीनी को लेकर प्रवेश भी खो दिया है। इससे निःसन्देह देश की समस्याएं और बढ़ गई है। फिलहाल, निर्यात करने वाले सभी देश, मार्केट के लिए दिए जाने वाले प्रवेश कानून में रद्दोबदल से तथा उत्पादनों के लिए विश्व दाम के उतार-चढ़ाव की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अब विषय यह है कि कितनी तेज़ी से ये देश बाज़ारों के बदलते हुए रूप या निर्यात के बदलते हुए तरीकों से अपने आप को ढालते हैं। फीजी इन परिवर्तनों को बहुत धीमी गति से अपना रहा है और यही वजह है कि सामाजिक खर्च और ज़्यादा बढ़ा है।

फीजी के वातावरण को लम्बे समय तक कायम रखना भी चिन्ता का विषय है। शहरी इलाकों में बढ़ती जनाबादी, व्यावसायिक, कृषि तथा टूरिज़्म और अन्य आर्थिक विकास के कारण तटवर्तीय इलाकों में लगातार दबाव में वृद्धि हुई है जिसके कारण वातावरण प्रक्रिया पर असर पड़ा है और जीव-जन्तुओं के रहने वाले स्थानों की क्षति हुई है। यह तटवर्तीय विकास, प्रदूषण, स्वच्छ पानी काम में लाने वालों से पानी की बढ़ती हुई मांग और संसाधनों को हो रही भारी क्षति इसके परिणाम है। तटवर्तीय इलाकों में विकास पर लगातार निगरानी न रखने के कारण यह पता लगाना कठिन हो गया है कि फीजी के तटवर्तीय इलाकों में किस हद तक क्षति और बर्बादी हुई है।

व्यवसायिक और कृषि क्षेत्रों से बिना ट्रीटड या अपर्याप्त ढंग से टीटड मैला पानी यानी वेस्टवोटर तथा सिवरज के मैल के कारण वातावरण तथा मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक असर पहुंच रहा है। वातावरण में परिवर्तन, संसाधनों के आर्थिक मूल्यों में कमी, दृष्टिगोचर

क्षति और मानव स्वास्थ्य के खतरे इन परिणामों का असर है। मैला पानी में जो प्रदूषण के पदार्थ हैं, उनमें शामिल है पायथोजन्स (माइक्रो ओर्गानिज़्म्स यानी छोटी किटाणु), पुष्टिकर पदार्थ, भारी-भरकम धातुओं, घातक रसायन, निष्कासित ठोस पदार्थ, तेल तथा ग्रीस। तटवर्तीय इलाकों में क्षति का एक और मुख्य कारण है अमहत्वपूर्ण ज़मीनों में ज़्यादा मात्रा में कृषि कार्यवाही जारी रखना और गलत ढंग से एक ही प्रकार की खेती करना।

फीजी में हाल के वर्षों में अधिकांश सामाजिक संकेत और खराब हुए हैं। देश में स्वास्थ्य, आमदनी और शिक्षा के संतोषजनक स्तर प्राप्त करने की प्रगति को मापने के लिए ह्यूमन डिवलप्मेंट इंडेक्स (हेच.डी.आई) सबसे स्वीकार्य तरीका है। 1975 में फीजी का स्तर 42 रहा जोकि 1997 में गिरकर 61 हो गया। 1990 के दशक में यह स्तर और भी ज़्यादा गिरा। 2005 यू एन डी पी ह्यूमन डिवलप्मेंट रिपोर्ट के आधार पर उसका वर्तमान स्तर 177 में से 92वें स्थान पर है।

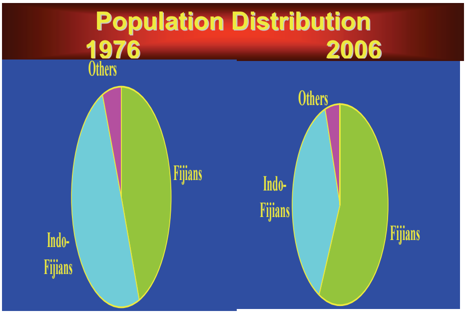


1987 के बाद से फीजी की जनाबादी के डेमोग्राफिक व्यवस्था में भारी परिवर्तन हुआ है। 1986 में कुल जनसंख्या बढ़ कर 715,375 रही जबकि 1996 में यह संख्या 775,077 रही और 2007 में 827,900 रही। यह भी देखा गया कि शहरी इलाकों की जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई और ग्रामीण इलाकों में फीजी के भारतीयों की संख्या में गिरावट हुई। शहरी इलाकों में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मूल इन्फ्रस्टक्चर जैसे, पानी, सड़कें और बिजली की व्यवस्थाओं की बढ़ती हुई मांग से दबाव और भी बढ़ गया। 1996 जनगणना से अगर इसका मिलान किया जाए तो 2007 की जनगणना के प्रस्तावित परिणाम से यह संकेत मिल रहा है कि शहरी इलाकों में आदिवासी फीजियन लोगों की संख्या में 49,427 से वृद्धि हुई है। उत्तरी विभाग में जनसंख्या 8,909 से गिरावट हुई और पूर्वी विभाग में 1,696 से गिरावट हुई। ग्रामीण इलाकों में फीजी के भारतीय लोगों की जनाबादी 36,708 से गिरी और केन्द्रीय विभाग की जनाबादी में 43,236 से वृद्धि हुई और पश्चिमी विभाग में जनाबादी 20,192 से बढ़ी।

शहरी इलाकों में बसने वाली प्रक्रिया के कारण गरीबी में वृद्धि हुई है। विभिन्न घरेलू आमदनी और खर्चों पर किए गए सर्वेक्षण हमें यह बताते हैं:

- 1997 में करीब 9 प्रतिशत हमारी जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे थी;
- 1990-91 में 29 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे थी;
- 2002-03 में लगभग 34.4 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे थी;
- अधिकांश गरीब लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, इनमें खासकर खेती करने वालों के समुदाय के भारतीय लोग हैं।

**फीगर 1: जातिए और ग्रामीण-शहर में गरीबी का विस्तार इस प्रकार**

| | ग्रामीण | | | शहर | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | फीजियन्स | फीजी के भारतीय | अन्य | फीजियन्स | फीजी के भारतीय | अन्य | |
| प्रतिशत लोग गरीबी में | 38.0 | 43.1 | 41.3 | 27.2 | 29.1 | 17.3 | 34.4 |

स्रोत: 2002/03 HIES Report

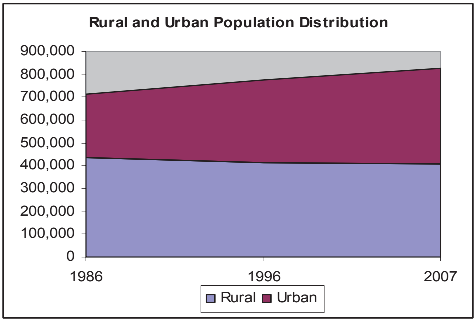


हेच आई ई एस आमदनी को लेकर गरीबी मापती है जोकि गरीबी का एक अंश है। 2003 में गरीबी और कठिनाइयों पर किए गए मूल्यांकन से यह संकेत मिला है कि फीजी के अधिकांश समुदाय अलग-अलग किस्म की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जो मूल सेवाओं की कमी पर आधारित है, जैसे, प्रारम्भिक स्वास्थ्य की देखरेख, शिक्षा, पानी, समाज में पूर्ण रूप से सामाजिक और आर्थिक भागीदारी के कम मौके और मूल संसाधन (नकद पैसा शामिल) की कमी। ये मूल ज़रूरतें एक विस्तृत परिवार, कोरो, गांवों, समुदायों या चर्च के पारम्परिक दायित्वों की पूर्ति के लिए आवश्यक है।

संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम डिवलप्मंट गोल 2 की पूर्ति करने के लिए फीजी भले ही सही मार्ग पर है- प्रायमरी स्कूलों के विस्तृत प्रारम्भिक शिक्षा और स्कूलों में विद्यार्थियों के भर्ती होने वाली दर साल 2000 के बाद से घटी है और यह अधिकतर आदिवासी फीजियन समुदाय के समक्ष देखने को मिल रहा है। 2004/2005 एम्प्लोएमंट और अनएम्प्लोएमंट सर्वे से यह पता चला है कि 5-14 वर्ष के बीच के आयु वाले 10 प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। ऐसा शायद इसलिए कि बच्चों के मातापिता बच्चों को स्कूल भेजने के लिए आर्थिक कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। स्कूल छोड़ने वालों के समक्ष नौकरी न मिलने की समस्या है या उनके पास हुनर की कमी है। सेकण्ड्री स्कूलों में बच्चों के भर्ती होने की संख्या में वृद्धि हुई है (अधिकतर लड़कियां) तो वहीं स्कूल छोड़ने वालों में बेरोज़गारी का कारण है, वर्तमान मज़दूर बाज़ार में नौकरी की कमी।

महिलाओं और भरण-भत्ता प्राप्त करने वाली महिलाओं को गरीबी का ज़्यादा खतरा है। इसका कारण है मज़दूर वर्ग में भेदभाव, तलाक में वृद्धि और परिवार टूटने की दर में वृद्धि। ये कुछ समस्याएं हैं जिनके कारण महिलाएं अपने पूर्व पतियों से मेन्टीनन्स पैमंट प्राप्त करने में समस्याएं महसूस करती हैं। सोशल वेल्फेयर विभाग से फेमली असिस्टंट स्कीम के मार्फत अधिकांश महिलाओं को मिलने वाला पैसा यह सच्चाई दर्शाता है कि महिलाएं वास्तव में गरीबी झेल रही हैं।

दोनों मुख्य जातिए दलों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही परम्परा के कारण बहुत कम महिलाएं ज़मीन की मालिक बनती हैं और ऐसा होने से महिलाएं किसी भी तरह की ज़मीन या किसी अन्य मिल्कियत की मालिक बनने से वंचित रह जाती हैं।

फीजी में महिलाओं, विक्लांग, अपंग लोगों तथा अल्पसंख्यक लोगों के साथ भेदभाव करना एक आम बात हो गई है। इस तरह का भेदभाव गम्भीर रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

फीजी के अधिकांश लोग कम खर्चे वाले घर या नीचले स्तर के घरों में रहते हैं और फीजी की 12 प्रतिशत जनाबादी झोपड़-पट्टियों में रहती हैं। ये बात और है कि फीजी में बहुत ज़्यादा ज़मीन है जो रहने वाले घरों के विकास के लिए उपलब्ध हो सकती हैं।

सभी प्रकार के घरों की कमी के कारण घरों का दाम और महंगा हो गया है जिसे बहुत कम मध्यवर्गी यानी मध्यम आमदनी प्राप्त करने वाले ही सह पाते हैं जबकि पहले ऐसा नहीं था। सार्वजनिक रूप से घर प्रदान करने वाली संस्थाएं जैसे, हाउज़िंग अथोरिटि तथा पी आर बी कम खर्चे वाले घर प्रदान करने की अपनी भूमिका में असफल रही हैं। ये संस्थाएं इसकी पूर्ति इसलिए नहीं कर सकीं क्योंकि वे उच्च कर्ज़ के स्तर की पूर्ति करने में लगी थीं।

मूल इन्फ्रस्ट्रक्चर (जैसे सड़क, पानी, बिजली तथा टेलीकोम्युनिकेशन सेर्विसस) की कमी ने फीजी में गरीबों की परिस्थितियों को और भी बढ़ा दिया है।

स्वास्थ्य सेवाओं में कई वर्षों के विकास के बावजूद, फीजी के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर जो सुधार की आशा की गई थी, वैसा सुधार नहीं हुआ। लोगों के जीवित रहने की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 2000 के वर्षों में 69.6 रही 2005 में गिरकर 68.5 हो गई।

वर्तमान स्थिति को और मोड़ देने के लिए निम्नलिखित जानकारियां दी जा रही हैः

- राष्ट्रीय पोवर्टी लाइन 2002 के लिए $8062.6 या लगभग $155.00 प्रति सप्ताह रहा;
- 2002 में पूर्ण समय की नौकरी में 55 प्रतिशत लोग रहें जिन्हें गरीबी की रेखा से नीचे का वेतन प्राप्त था (नारसी 2006);
- 12.5 प्रतिशत जनसंख्या झोपड़-पट्टियों में रहती है;
- 22,670 को 2005 में फेमली असिस्टंट स्कीम का पैसा मिलता था (कम से कम प्रति माह $60 और ज़्यादा से ज़्यादा $120 प्रति महीना था);
- 13,000 ज़मीन की लीसों की अवधि समाप्त हो गई तथा अगले दस सालों में और ज़्यादा लीसों की अवधि समाप्त हो जाएगी। प्रत्येक ज़मीन की लीस जिसकी अवधि समाप्त हुई और जिसे नई नहीं की गई, उस ज़मीन में रहने वाले कम से कम 5 परिवार (जिसमें अवसत 5 सदस्य हैं) बेघर हो गए और वेदूसरे स्थान पर बस गए। गन्ना कटैया के रूप में खेतों में काम करने वाले, इस देश के सबसे गरीब लोगों में से हैं।
- सेव द चिल्ड्रन्स फण्ड (फीजी) के एक अध्ययन से पता चला कि स्कूल छोड़ने वालों में से 66 प्रतिशत छात्र गरीबी के कारण स्कूल छोड़ चुके हैं।

स्रोतः पोवर्टी इन फीजी टुडय, केविन जे बार (एक्रिया)

लम्बे समय वाली नौकरी के मौके की सुरक्षा जिसके साथ अच्छा वेतन हो, ही लोगों को गरीबी के फंदे से बाहर निकाल सकता है। सरकारी संचालन की वर्तमन समस्याओं तथा राजनीतिक अस्थिरता के कारण अर्थ व्यवस्था स्थिर है जिसकी वजह से गरीबों के लिए कम नौकरी के मौके तथा अपर्याप्त सहायता है, जिसके कारण ये लोग वर्तमान मौकों से ज़्यादा लाभ नहीं उठा सकते। इस स्थिति को और भी खराब करने के लिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पारम्परिक सहायता व्यवस्था कमज़ोर हो रही है, जिसके कारण और ज़्यादा लोगों को, खासरूप से वृद्ध लोगों को वेल्फेयर की सहायता की ज़रूरत पड़ने लगी है।

इन सभी कारणों से फीजी के कई लोग अपने को अकेला, बेकार तथा तिरस्कृत समझने लगे हैं। ऐसे लोगों में दूसरों पर निर्भर होने की, शक्तिहीन तथा निराशावादी की भावना जन्म लेती है जिसके कारण वे अपने को अलग समझने लगते हैं। उदाहरणार्थ, फीजी में भारतीय महिलाओं में आत्महत्या की दर अब विश्व में तीसरा सबसे ऊंचे स्थान पर है।

फीजी में इस वक्त जो छवि है वो 1970 में प्राप्त स्वतंत्रता के समय लोगों द्वारा संजोए गए सपनों के मिलान में बहुत फर्क है।

# भाग २

## फीजी की समस्याओं के कारण - कुछ आलोचनात्मक सवाल

सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के पीछे अकसर कुछ कारण होते हैं- इनमें सबसे तत्कालीन है (डाक्टर आया ही नहीं), इन्टरमीडियट कारण (वह लड़की आई नहीं क्योंकि उसे गाड़ी नहीं मिली) और इससे बढ़कर कारण (स्वास्थ्य सेवा की कुल राष्ट्रीय मांग से जूझने के लिए संसाधनों के साथ पूर्ण रूप से प्रशिक्षित डाक्टर पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं)। इससे भी ज़्यादा और भी मुख्य स्तर पर कुछ और भी कारण होंगे, लेकिन सबसे आवश्यक तथ्य (तथ्य जो कई सेक्टरों पर प्रभाव डालते हैं) सामाजिक तथा आर्थिक विकास में बाधक होते हैं। इन तथ्यों का पता लगाना चाहिए और उन्हें पूर्ण रूप से समझना ज़रूरी है अगर लम्बे समय के लिए परिवर्तन में सफलता प्राप्त करनी है। नीचे दी गई पंक्तियों में अति गम्भीर और मुख्य कारणों का पता लगाने का प्रयास किया गया है- अकसर स्वयं पुनःदबाव डालने के तरीकें- फीजी के समक्ष वर्तमान में कई समस्याएं। पहचानी गई समस्याएं सवालों के रूप में नीचे दी गई हैं:

**संसदीय प्रजातंत्र में कमज़ोरी, खासकर संवैधानिक व्यवस्थाएं और अप्रिय राजनीतिक व्यवहारों के कारण।**

क्या आप सोचते हैं कि वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाएं (खासकर सम्प्रदायिक मतदान सूची और बहु-पार्टिय मंत्रीमण्डल व्यवस्था वाली सरकार) के कारण हो सकती है कि समुदायिक और धार्मिक विवाद खासकर राजनीतिक स्तर पर और भी बढ़े हैं? किस तरह से और ज़्यादा छूट राजनीतिज्ञों को दी जाए ताकि वे फीजी की प्रगति के लिए मिलकर काम और प्रतिनिधित्व करें, न कि सिर्फ एक खास जातिए दिलचस्पी की ओर ध्यान दे।

क्या आप सोचते हैं कि खासकर 1987 के बाद राजनीतिक, जातिए तथा धार्मिक तनाव से मुख्य समुदायों के बीच विश्वास का आम स्तर कम हो गया है? क्या आप स्वीकार करते हैं कि ओल्टेनेटिव़ व़ोटिंग, कोम्युनल ब्राउन्ड्री सिस्टम के साथ मिलकर एक्सट्रीमिस्ट पार्टियों का पक्ष करती है (क्योंकि मोड्रट राजनीतिक पार्टियां अपना प्रथम प्रेफरन्स अन्य मोड्रट पार्टियों को नहीं देती हैं, जो उनके साथ बहुत ही नज़दीकी से मत के लिए होड़बाज़ी करती हैं)?

क्या और न्याय के लिए वर्तमान चुनाव प्रणाली व्यवस्था को बदलना चाहिए (जिसमें प्रत्येक पार्टी को कितना मत मिलता है, यह दर्शाता है)? और क्या विकल्प है (प्रोपोशनल रीप्रिसेन्टेशन शामिल है) जिसपर ध्यान दिया जाना है?

संविधान के तहत सत्ता को बांटने की व्यवस्था जिसे सरकार वैधानिक रूप देने का प्रयास कर रही थी, क्या वह असरकारक साबित नहीं हो सकी?

उत्तरदायित्व व्यवस्था की आलोचना अपर्याप्त कहकर बताया गया है। प्रजातंत्र संवैधानिक दफ्तर जैसे संसद, न्याय प्रणाली तथा अन्य स्वतंत्र संवैधानिक दफ्तर जैसे, ओडिटर जेनरल के काम करने की क्षमता और भूमिका निभाने का काम चर्चा में आया। सभी सेक्टरों में ईमानदारी, खासरूप से नैतिक स्तर को असर में लाते वक्त, ताकि सार्वजनिक अफसरों जैसे संसद सदस्यों, जजों और मेजिस्ट्रेट, संवैधानिक दफ्तर सम्भालने वालों और उच्च सरकारी कर्मचारियों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जा सके, के तहत उनकी सेवा वाली संस्थाओं पर से विश्वास और सम्मान घट गया है। क्या और कार्यकुशल कदम उठाना ज़रूरी है ताकि सरकारी संस्थाओं और सार्वजनिक अफसरों को पारदर्शी और ज़िम्मेदार ठहराने के लिए मज़बूती प्रदान किया जा सके?

फीजी में राजनीतिक और सार्वजनिक सेक्टरों में नेतागिरी में कमज़ोरी की समस्या कैसे सुलझ सकती है, जहां दफ्तरों का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के लिए गलत ढंग से होता है? जनता का मानना है कि और सक्रिय कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि भ्रष्टाचार से निपटा जा सके। अभी तक अपराधिक न्याय प्रणाली भ्रष्टाचार वाले विषयों से निपटने में असमर्थ रही है जहां यह देखा गया कि 1990 के सालों में नेशनल बैंक ओफ फीजी की आर्थिक संकट की रोकथाम का प्रयास असफल रहा तथा 2001 के आम चुनाव से पूर्व कृषि धांधली में उलझे लोगों को सज़ा दिलाने में देर हुई। भ्रष्टचार से जूझने वाली संस्था, फीजी इंडिपेन्डंट कमीशन की स्थापना तो अभी हाल में की गई है। क्या इस संस्था यानी फाइकेक की सार्थकता, भूमिका तथा संचालन को लेकर और मज़बूती की ज़रूरत है? क्या सभी सेक्टरों में भ्रष्टाचार से जूझने के लिए और कानूनी परिवर्तन की ज़रूरत है?

एक स्वतंत्र समाचार माध्यम की भूमिका किस तरह से प्रजातंत्र को बढ़ावा तथा विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता को बढ़ावा दे सकता है?

क्या आप सोचते हैं कि आदिवासी फीजियन समुदायों के बीच भिन्नताओं से समुदायों के बीच विश्वास का स्तर और गिर गया है? क्या आप सोचते हैं कि समुदायों के बीच बढ़ती हुई भिन्नताएं, असहनशीलता तथा आपसी राजनीतिक लड़ाई गिरती हुई सामाजिक स्थिति, अर्थ व्यवस्था और सम्पूर्ण सरकारी संचालन की गिरती हुई फीजी की हालत को रोकने में क्या देश को कोई योगदान मिला है?

ज़रूरत है मानवाधिकारों के सिद्धांतों को असरकारक रूप से लागू करना जो निर्णय लेने वाली प्रकिया में एक सकिय सामाजिक भागीदारी निभा सके। उदाहरणार्थ, एक-दूसरे से मेलमिलाप की स्वतंत्रता और विचार व्यक्त करने की व्यवस्था जिनसे विवादों से भरे हुए न मिलने वाले विचारों के प्रति ज़्यादा सहनशीलता दिखा सके जोकि एक अच्छी और आवश्यक सरकार के लिए ज़रूरी है। क्या फीजी के लिए ऐसा ज़रूरी है? क्या मानवाधिकारों के आम सिद्धांतों पर और ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि प्रजातंत्र को बरकरार रखने के साथ ही उसे बढ़ावा मिल सके?

**नागरिकता, राष्ट्रीय पहचान, मानवाधिकार तथा नागरिकता वाला समाज।**

फीजी के पास एक राष्ट्रीय पहचान को लेकर एक ठोस भावना नहीं है जिसके ज़रिए विभिन्न समुदायों में राष्ट्रीय भावना नहीं है। स्कूलों, कोम्युनल एलेक्ट्रोल सिस्टम तथा जातिए राजनीतिक पार्टियां जैसी समस्याओं में जातिए विभाजन तथा धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों को और मज़बूती मिली है जबकि इनके स्थानों पर हमें एक पहचान और अपनेपन की भावना की ज़रूरत है। 1997 संविधान में नीहित एक राष्ट्रीय नाम "फीजी आयलेण्डर" को पहचानने में जो असफलता मिली है, वह राष्ट्रीय पहचान की कमज़ोरी का चिन्ह है।

यह कमज़ोरियां, आदिवासी फीजियन लोगों की राष्ट्रीय पहचान और जातिएता की भावनाओं के कारण और भी प्रबल हुई है। जहां आदिवासी फीजियन लोग यह विश्वास करते हैं कि देश में आदिवासी दर्जा और ज़मीन उन्हीं को पहले मिली है। और यही वजह है कि वे इस देश में प्रथम अधिकार चाहते हैं तथा अन्य समुदायों की

दिलचस्पियों से पहले अपना हित चाहते हैं। इन्हीं विश्वासों के बलबूतों पर वे यह समझने लगे हैं कि इस देश की राजनीतिक ताकत भी उन्हीं को मिले जहां वे चाहते हैं कि आदिवासी फीजियन लोगों को देश में राजनीतिक नेतागिरी करने की गारण्टी मिले। इन्हीं ख्यालों और विश्वासों के कारण वे असुरक्षित महसूस करते हैं तथा अन्य समुदायों से भय खाते हैं, जैसे फीजी के भारतीय समुदाय से उन्हें भय रहता है कि ये लोग उनकी ज़मीनें ले लेंगे और उन्हें विकास के मौकों से वंचित कर देंगे।

एस डी एल स्वामित्व वाली सरकार की 2020 तक आदिवासी फीजियन लोगों की भागीदारी फीजी की आर्थिक, सामाजिक तथा पेशेवर विभागों में बराबर '50/50' यानी आधो-आध वाली योजना में फीजियन लोगों की ये दिलचस्पियां उभारी गई हैं। 2006 में सरकार को दी गई फीजी ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस योजना में ऐसे पहलु हैं जो संविधान तथा सामाजिक न्याय कानून की ज़रूरतों से मेल नहीं खातें, जो दल और लोगों के वर्गीकरण के लिए अर्फेमेटिव़ एक्शन का कानूनी ढांचा है। देश के अन्य समुदाय यही सोचता है कि उन्हें अलग कर दिया गया है, लेकिन आदिवासी फीजियन लोग ठोस रूप से विश्वास करते हैं कि इस अर्फेमेटिव़ एक्शन प्लेन के लम्बे समय वाले कार्यक्रमों से संविधान के तहत नीहित उनकी दिलचस्पियों की ज़रूरतों की पूर्ति होती है और जो राष्ट्रीय हित में शांति, सुरक्षा तथा न्याय के लिए ठीक है। सभी अर्फेमेटिव़ एक्शन कार्यक्रमों के लिए आगे बढ़ने का तरीका यही होगा कि सभी समुदायों के बीच सामंजस्य का विस्तृत विकास, विचार विमर्श और पुनःविचार ज़रूरी है।

फीजी के भारतीय लोगों का विश्वास है कि उन्हें अपनी ही मातृ-भूमि में विदेशी माना जाता है और वे अपने देश में दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। उनकी ये असुरक्षा की भावना और भी बढ़ जाती है जब उनसे ज़मीन काम में लाने की सुरक्षा छीन ली गई, स्वामित्व की भावना कमज़ोर की गई। इन्हीं कारणों से अब फीजी के भारतीय लोग अपना भविष्य शिक्षा, व्यवसायिक मौके तथा विदेश में बसने में देख रहे हैं।

पिछले 20 वर्षों में मंदिरों तथा अन्य धार्मिक चिन्हों को जलाने वाली घटनाएं, धार्मिक असहनशीलता को स्पष्ट करती है। राजनीतिक तथा धार्मिक नेताओं के द्वारा इस तरह की गतिविधियों का खण्डन न करने से अन्य समुदायों में यह विश्वास और ठोस हो गया है कि फीजी के भारतीयों और अल्पसंख्यक समुदायों के धर्मों को सम्मान नहीं मिल रहा

है तथा चुप रहकर असहनशीलता को समर्थन प्राप्त हो रहा है।

1987 के बाद से फीजी में जो चार सैनिक सत्ता पलटाव हुए हैं, उनके ज़रिए खासकर फीजी के भारतीय लोगों को विदेश बसने में प्रोत्साहन मिला है और यही कारण है कि देश में योग्य और अनुभवी लोगों की कमी हुई है तथा 1980 के दशक में भारतीयों की ज़्यादा से ज़्यादा जनाबादी गिरकर 21 शताब्दी में अल्पसंख्यक स्तर पर हो गई है।

फीजी में अल्पसंख्यक समुदायों की अपनी-अपनी असुरक्षा की चिन्ता है और वे पहचान तथा अपनेपन की कमी का एहसास कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, सोलोमन आयलेण्ड्स, वनुआतू, तोंगा तथा सामोआ के मूल समुदायों जो 1987 से पूर्व आदिवासी फीजियन्स के साथ पहचाने जाते थे, वे 1997 संविधान आने के बाद से "जेनरल एलेक्टर्स" या जातिए अल्पसंख्यक के रूप में पहचाने गए।
अर्ध-यूरोपियन समुदाय जो मूल रूप से आदिवासी फीजियन वंशज से जुड़े हुए हैं और जो फीजियन सभ्यता और संस्कृति को बांटते हैं, उन्हें भी एक अलग जातिए दल के रूप में पहचाना जा रहा है।

राष्ट्रीय पहचान की भावना और ठोस करने के लिए हमें अब और क्या करने की ज़रूरत है ताकि फीजी के सभी समुदायों में जो असुरक्षा और पहचान की भावना की कमी है, उनका सामना किया जा सके?

एक अच्छी सरकार प्रजातंत्र, मानवाधिकार, सुरक्षा, वातावरण तथा सामाजिक और आर्थिक विकास को लेकर नागरिकों के बीच उत्पन्न ठोस सहनशीलता की प्रवृति, फीजी में एक महत्वपूर्ण विकास रहा है। दिसम्बर 2006 में आर एफ एम एफ ने सरकार को हटाया था जिसके कारण समाज के कई नेताओं ने कड़ी आलोचना की थी तथा सुरक्षा दलों के इस बर्ताव पर राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय रूप से लगातार बौछार आते रहें। एक अच्छी सरकार के महत्व के लिए ज़रूरी है कि फीजी में कायम बहु-वर्गीय समाज को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। जनता द्वारा नीति निर्धारण में भाग लेने वाली प्रक्रिया को और भी मज़बूत करने की ज़रूरत है और ऐसा तभी होगा जब नागरिक समुदायों और संस्थाओं की भूमिकाओं को प्रोत्साहित करने की भूमिकाओं को स्वीकार किया जाएगा। इसमें ऐसे कानूनों में परिवर्तन लाने की ज़रूरत होगी जो नागरिक समुदायों की गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए निर्णय बनाने वाली प्रक्रिया में सहायक हो ताकि देश का विकास हो सके।

## कमज़ोर संस्थाएं तथा "रूल्स ओफ द गेम" यानी खेल के नियम

सामाजिक व्यवस्थाओं के संचालन के लिए हर समाज के पास अपने कायदे और कानून हैं। इसमें एक सरकार चुनने की संवैधानिक व्यवस्था, न्याय प्रणाली की स्थापना, बाज़ार संचालित करने के नियम (उदारहण, स्टोक एक्सचेंज कानून, व्यवसायिक कानून, बैंकिंग प्रक्रिया, उपभोक्ता सुरक्षा कानून तथा सरकारी नियम जैसे, दामों के नियंत्रण और टाऊन प्लेनिंग कानून) शामिल हैं। ये खेल के नियम सामाजिक और आर्थिक व्यवहार पर ताकतवर तथा लगातार प्रभाव डालते हैं। पूर्ण रूप से यह कहा जा सकता है कि यह व्यवहार व्यवसायों को खतरा मोल लेने तथा नई पूंजी लगाने की इच्छा को बढ़ाने का पता लगाता है। अगर व्यवसाय विफल होते हैं, तो इससे यह भी पता चलता है कि घाटा कैसे होता है। अच्छे नियम व्यापारिक व्यवहार या खतरे लेने को बढ़ावा देता है जबकि वो साथ-साथ उन कर्मचारियों को भी सहयोग देता है जो अपनी नौकरी खो देते हैं ("सोशल सेफ्टी नेट्स") अगर व्यवसाय विफल हो जाते हैं।

फीजी में ऐसे ठोस सबूत हैं कि ऐसी कई संस्थापिक व्यवस्थाएं हैं जो व्यापारियों के लिए एक सफल व्यवसाय चलाने के संसाधनों की ज़रूरतों के रास्तों पर कठिनाइयां पैदा करती हैं जैसे कि, मुख्य योग्य मज़दूर, ज़मीन, विदेशी मुद्रा, संचालन उत्पादन जैसे, इन्शुरन्स या फोवर्ड फोरन एक्सचेंज ठेकें। इन संसाधनों को काम में लाने के लिए गरीब लोगों को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन्हें माइक्रोक्रेडिट सुविधाएं, नए बाज़ारों पर जानकारी या नए कृषि तकनीक या उत्पादनों के लिए आसानी से जानकारी नहीं मिलती है। दोनों समुदायों के अधिकांश गरीब लोगों के पास शैक्षिक मौके और जीविका चलाने के लिए पर्याप्त ज़मीन के दूसरे मौके भी आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें सामाजिक सामानता और आर्थिक संचालन के मौके नहीं मिलते हैं। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं?

फीजी की सरकार चलाने के लिए वर्षों से जो विस्तृत प्रकार के कानूनों का विकास हुआ है उनसे एक सार्थक, लगातार आसानी से उपलब्ध होने वाली सरकारी ढांचा देश को उपलब्ध नहीं हो सकी है। आर्थिक और सामाजिक समझौते को बढ़ावा देने के लिए एक कानूनी ढांचे की पुष्टि के लिए क्या ज़रूरी है ना कि उसके कार्य में कोई बाधा आए। इस ढांचे को ताकतवर बनाने के लिए अदालतें जो भूमिका निभाती हैं क्या इन्हें और भी मज़बूत नहीं बनाया जा सकता?

फीजी में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की संस्थापित ढांचे को और कैसे सुधारा जा सकता है? उदाहरण के तौर पर देखिए रिसर्व बैंक तथा फीजी वेजस काउन्सिल की भूमिकाएं। किस तरह से उदाहरण के तौर पर सरकार प्रायवट सेक्टरों के साथ साझेदारी व्यवस्थाओं का विकास कर सकती है?

वेट तथा इन्कम टेक्स शेड्यूल, नेटिव़ लेण्ड ट्रस्ट बोर्ड द्वारा ज़मीन उपलब्ध करने की प्रक्रिया का कानूनी संचालन ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो "खेल की नीतियां" तैयार की है जिनसे फीजी में आमदनी के वितरण के तरीकें दिखाई देते हैं। हाल के सर्वेक्षण यह उल्लेख करता है कि समाज के बीच विश्वास की आम धारणा के स्तर तथा आमदनी के वितरण में समानता के बीच सकारात्मक सम्बन्ध है। भरोसा विश्वास व्यक्त करने का एक मूल्य है कि अन्य लोग आपके नैतिक समुदाय का एक हिस्सा हैं और इन्हीं आधार पर अजनबियों के साथ सहकारिता बनाई जा सकती है। जिन सामाजों में भरोसा की आम धारणा होती है, वहां और ज्यादा आमदनी की समानता देखने को मिलती है। सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि किसी भी समाज में जहां आम धारणा वाले भरोसे के स्तर टूट चुके है, ऐसे समाज में भ्रष्टाचार में वृद्धि तथा और ज्यादा असमानता (क्योंकि सत्ताधारी पक्ष गरीबों को उन के नैतिक समुदाय का एक हिस्सा नहीं मानती) होती है। क्या आप समझते हैं कि फीजी में आमदनी का वितरण बहुत ज़्यादा असामान है और एक न्यायसंगत आमदनी के वितरण से समाज के बीच विश्वास के स्तर में वृद्धि होगी और तनाव कम होंगे?

**फीजी में अत्याधिक प्रभुत्व वाली सरकार की भूमिका**

सरकार को सिर्फ उन्हीं विषयों पर ध्यान देना चाहिए जो उन्हें करना है और ठीक तरह से करना है। क्या आप यह स्वीकार करते हैं कि सरकार को अपनी भूमिकाओं की ज़रूरतों पर फिर से ध्यान देना चाहिए और उसे सिर्फ उन्हीं विषयों पर पुनःगौर करना चाहिए जो सिर्फ उन्हें करना है जिसके बाद ही यह वो पुष्टि करे कि वह जो कर रही है, ठीक ही कर रही है?

आर्थिक क्षेत्र में सरकार की यह भूमिका है कि वह मिल्कियत के अधिकारों को स्पष्ट करे (जैसे, यह निर्णय बनाए कि लीस के मालिक तथा ज़मीन की लीस किसकी हो और अन्य चीज़ें) यह भी पुष्टि करें कि इसके लिए एक सार्थक कानून हो, जैसे कि एकाधिकार की ताकत को सीमित करना तथा न्यायपूर्ण वेतन को कायम रखना और

सार्वजनिक सेवाएं जैसे सेना तथा पुलिस (और योग्यता साधन जैसे शिक्षा) यही कुछ चीज़े हैं जो सरकार को ही प्रदान करना है। सरकार की यह भी ज़िम्मेदारी है कि वह देखे कि आमदनी का समान तौर पर वितरण हो, पुरूषों-महिलाओं के अधिकारों में समानता हो तथा मानवाधिकार प्राप्त हो ताकि यह पुष्टि हो सके कि वर्तमान गतिविधियों को लम्बे समय तक रखकर भावी पीढ़ियों के लिए वातावरण सुरक्षित किया जा सके। इनमें कुछ ऐसी भी गतिविधियां हैं जो अच्छी हैं लेकिन उन्हें प्रायवट सेक्टरों के लिए छोड़ दी जाती हैं। वर्तमान में फीजी की सरकार कई गतिविधियों में उलझी हुई है जिन्हें शायद प्रायवट सेक्टरों के लिए छोड़ देना ही बेहतर है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा वर्तमान में आवश्यक प्रायवट सेक्टरों की गतिविधियों में "लोक्टड अप" यानी पैसा उसी में खर्च होता है (जैसे कि टेलिकोम्युनिकेशन्स, पावर जेनरेशन आदि) ऐसा होने से सरकार के पास अतिरिक्त इन्फस्ट्रक्चर जैसे सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों की सेवाओं में खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है।

दूसरी ओर सरकार ने कुछ ऐसे क्षेत्रों को नज़रान्दाज़ किया है जिनपर उसे ध्यान देना चाहिए था। फीजी की 90 प्रतिशत ज़मीनों के सम्पत्ति अधिकार का पता लगाने की अयोग्यता उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी रही है। फीजी में सम्पति अधिकार सबसे बड़ी समस्या रही है। यह समस्या ज़मीनों के स्वामित्व को लेकर नहीं है क्योंकि इनके मालिक आदिवासी फीजियन्स ही रहेंगे। यह समस्याएं ज़मीन की लीस की दिलचस्पियों की प्रणाली को सामान्य बाज़ार में लागू करने की अक्षमता को लेकर है जिससे कि आर्थिक और सामाजिक दोनों उद्देश्यों के लिए और ज़मीनें उपलब्ध हो सके (जैसे कि, रहने वाले घरों की व्यवस्था)। जबकि फीजी में आर्थिक गतिविधियों में ज़मीन एक महत्वपूर्ण भाग अदा करती है तो वहीं अब ये विकास में मुख्य बाधा बन चुकी हैं।

अन्य क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं, उनमें शामिल हैं बुरी तरह तैयार किए गए कानून। व्यापार के लिए कानूनी ढांचा कमज़ोर है। बहुत पुराने कानूनों के तहत व्यापार संचालित होते हैं और अब इन्हें नए आधुनिक तरीकों की ज़रूरत है। योग्यताओं में और निखार लाने के लिए अपर्याप्त मौके हैं। क्या आप यह स्वीकार करते हैं कि फीजी में मुख्य हुनर की कमी जैसे कार्पेन्ट्री, इंजीनियरिंग, कोम्प्युटर का कम ज्ञान, व्यापार का ज्ञान/योग्यताएं तथा पेशेवर हुनर जैसे डाक्टर, अकाउंटन्ट्स तथा कई अन्य जो विदेश आकर्षित हो गए हैं, के कारण देश में धीमी प्रगति की दर प्राप्त हुई है और इस समस्या को सुधारने के लिए क्या सुधरी हुई शिक्षा तथा वोकेशनल ट्रेनिंग कार्यक्रमों की ज़रूरत है?

राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में फीजी में कानून लागू करने, संविधान बरकरार रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षित करने की ज़रूरतों के लिए कैसी संस्थापित ढांचे की ज़रूरत है? देश में सत्ता पलटाव की परम्परा को खत्म करने के लिए किस तरह के कदम की ज़रूरत है? खासतौर से फीजी मिलिट्री फोसर्स की भावी भूमिका क्या होनी चाहिए? फीजी पुलिस फोर्स की क्या भूमिका होनी चाहिए? राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कैसी प्रणाली और मेलजोल की ज़रूरत है? सरकार की विभिन्न संस्थाओं (जैसे कि अदालतें, सेना, पुलिस तथा प्रीज़न्स) द्वारा कैसी भूमिकाएं निभाने की ज़रूरत है ताकि देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारी जा सके और कानून लागू किए जा सकें?

कम्पनियों के निजीकरण तथा सार्वजनिक व्यापारों में बदलाव लाने वाले कदम को किस ढंग से और बढ़ावा दिया जा सकता है? क्या कुछ खास संस्थाएं हैं जिन्हें इस तरह के बदलाव के लिए उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए?

वर्तमान में सरकार जो कार्य करती है क्या उसमें नागरिक समाज की और ज़्यादा भूमिका निभाने के मौके हैं?

जबकि आर्थिक संचालन और सार्वजनिक सेवा की सुधार को लेकर कुछ अच्छी प्रगति प्राप्त की गई है तो वहीं इन परिवर्तनों के संचालन और उन्हें जारी करने को लेकर कुछ विषय उठाए गए हैं। सार्वजनिक सेवा में संचालन क्षेत्र के असमानता तथा सम्पूर्ण आकार को लेकर कुछ चिन्ताएं व्यक्त की गई हैं। सार्वजनिक सेवा में कार्य संचालन के सुधार के लिए कौन सा कदम ज़रूरी है? सार्वजनिक सेवा के लिए सम्पूर्ण संचालन ढांचे को और मज़बूत कैसे बनाया जा सकता है? क्या आर्थिक संचालन और बजट निर्धारण में और ज़रूरतों के लिए स्थान है? क्या इसमें सही आकार एक विकल्प है जिसपर गौर करने की ज़रूरत है? सार्वजनिक सेवा में विभिन्न पहलुओं को लागू करने के अगले कदम क्या होने चाहिए?

सार्वजनिक सेवा के स्तर तथा उससे और ज़्यादा लाभ उठाने में सुधार लाया जा सकता है? स्थानीय स्तर पर एक सुधरी हुई सेवा प्राप्त करने के लिए किन परिवर्तनों की ज़रूरत है? इनमें क्या कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिन्हें सुधार के मिलान में प्राथमिकता देनी चाहिए (उदाहरण, स्वास्थ्य सेवा, पानी सप्लाई)।

## अनुपयुक्त और/या असामान्य नीतियां

*बड़ी आर्थिक नीतियों से व्यापारिक वातावरण पर ठोस प्रभाव पड़ा है।*

2001 के अन्त समय से आर्थिक स्थिति को जानबूझ कर ज़बरदस्त शुरूआत देते हुए सरकार ने बजट के घाटे को और बढ़ा दिया तथा प्रायवट सेक्टर में पूंजी लगाने के स्तर को कम करते हुए सार्वजनिक पूंजी से इसकी पूर्ति की। इन नीतियों को लेकर अच्छे ख्यालों पर कोई संदेह नहीं लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि इस तरह के कदम से सिर्फ आंशिक यानी कुछ ही सफलता मिली है। हालांकि इससे आर्थिक गतिविधियों के स्तर कायम रहे खासकर सत्ता पलटाव के बाद की तत्कालिक अवधि की खपत को सहायता मिली है लेकिन इससे पूंजी में वृद्धि नहीं हुई है। वेतन तथा तनख्वाह के आकार के कारण सरकार की पूंजी लगाने की क्षमता संकुचित हो गई है। वह सिर्फ आवश्यक या मुख्य खर्च के लिए अतिरिक्त पैसा निर्धारित कर सकती है और वो भी उस हद तक कि वह सरकारी कर्मचारियों के आकार घटा सके (या अवसत वेतन तथा तनख्वाह स्तर)। इस काम के लिए खर्च का नियंत्रण असामान्य रहा है।

आर्थिक स्थिति का विस्तार (आर्थिक घाटा 2001-2003 के बीच का जी.डी.पी अवसत 6.5% रहा) लम्बे समय तक कायम रहा क्योंकि सरकार के लिए एफ एन पी एफ से पैसा निकाल कर वार्षिक घाटे की पूर्ति के लिए आसान हो गया था। इससे तीन अप्रिय परिस्थितियां पैदा हुईं। सार्वजनिक घाटा 2001 में 44% जी डी पी से बढ़कर 2006 में जी डी पी का 52% हो गया जिसके साथ ही वार्षिक घाटे की पूर्ति का भार भी बढ़ गया। एफ एन पी एफ में पूंजी लगाने वालों को और विस्तृत मौके नहीं मिलें (जिसके कारण खतरा कम रहता है); और ज़्यादा महत्वपूर्ण यह जानना है कि यह आर्थिक विस्तार एक संतुलित बाहरी अकाउंट कायम रखने में सार्थक नहीं रहा है। इस तरह के अतिरिक्त खपत वाले खर्च से बेलंस ओफ पैमंट पर अनावश्यक भार पड़ा है। 2005 के मध्य तक सरकार ने योजनाओं में बदलाव की घोषणा कीः जिसका ध्यान खासरूप से आर्थिक मज़बूती तथा निर्यात को बढ़ावा देने पर गया। हाल में, 2007 की शुरूआत में रिसर्व बैंक ओफ फीजी ने देश के विदेशी

मुद्रा रिसर्व को सुरक्षित करने के लिए विदेशी मुद्रा के नियन्त्रण को और सख्त कर दिया। प्रायवट सेक्टर को व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कर्ज़ पर भी सीमाएं निधारित हुईं।

2000 कू के तुरन्त बाद आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जानबूझ कर आर्थिक शर्तें ढीली कर दी गई थी। आर्थिक नीतियों के प्रभाव से हुए विस्तार के नियन्त्रण के भारी अंश को सन्तुलित करने के लिए आर्थिक नीतियों को भी सख्त कर दी गई थीं। छोटे शब्दों में, इस अवधि के अधिकांश समय में दोनों आर्थिक तथा पैसों वाली नीतियां एक दूसरे से मेल नहीं खाती थीं।

फिक्सड एक्सचेंज रेट के कारण हमारी अर्थ व्यवस्था को बाहरी ताकतों को लाभ उठाने का मौका मिला है। एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो आसानी से रातोंरात लागू नहीं किया जा सकता, से आर्थिक व्यवस्था के मार्फत फोरन एक्सचेंज के खर्चों से मिली छूट का विस्तार हो सकता है जिससे फोरन एक्सचेंज के खर्चों में हुए परिवर्तन से सभी सतर्क हो सकें।

फीजी फोरन एक्सचेंज नियंत्रण को फिक्सड एक्सचेंज रेट के अतिरिक्त कायम रखता है। लेकिन इससे व्यापारियों को विदेशी मुद्रा के सीमित लाभ के मौके प्राप्त होते हैं तथा आवश्यक संचालन उत्पादन के खतरें तथा अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक बाज़ार में शामिल होने के लिए देश के मौके सीमित हुए (इससे फीजी को उसके विकास के लिए जो पैसा ज़रूरी, उससे सहयोग मिले)। देश के बड़े बड़े आर्थिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत यह एक अन्दुरूनी असमानता है। क्या आप सोचते हैं कि बड़ी आर्थिक नीतियों की व्यवस्था अन्दुरूनी रूप से और असरकारक होनी चाहिए?

*बदलती हुई बाहरी पस्थितियों के साथ अपने आप को जल्द से जल्द ढालने की अति आवश्यकता है।*

चीनी और कपड़ा व्यवसाय के लिए मुख्य प्राथमिकता वाले बाज़ारों को खोने (या खोने के खतरे) से देश की अर्थ व्यवस्था और कमज़ोर हो गई है और यही फीजी की वर्तमान आर्थिक समस्याओं का प्राथमिक "कारण" है। यह बेकार है कि हम लोग बदलती हुई बाहरी परिस्थितियों को लेकर शिकायत करते हैं। बाहर के और भी देश इसी तरह के बाहरी परिवर्तन की

परिस्थितियों का सामना करते हैं जैसे कि उन्हें पेट्रोलियम उत्पादन के लिए ज़्यादा दाम भरना पड़ता है (सम्भवतः एक स्थाई व्यवस्थित परिवर्तन महत्वपूर्ण तेल उत्पादन के बाज़ारी दाम में होता है) इसी तरह के उच्च दाम कुछ अन्य उत्पादनों, ई यू के बदलते कानून तथा डब्लू टी ओ के दबाव के तहत बाज़ार में प्रवेश करने वाले परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। इन्हीं परिवर्तनों के कारण सभी देशों को और ज़्यादा खुले रूप से तथा और गहरी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्य विषय है कि थोपे गए इन परिवर्तनों की परिस्थितियों के साथ सभी देश किस तरह से सामना कर रहे हैं। जो देश इन बदलती हुई परिस्थितियों का जल्दी से सामना कर लेती हैं, मौके उनका साथ देता है यानी वे पहले फायदा उठाते हैं। अभी तक फीजी ने इस परिवर्तन से "धीमी गति से ढाला" है। फीजी के लिए चुनौती यह है कि वह और जल्द अपनी आर्थिक व्यवस्था को पुनःव्यस्थित करने के लिए शिक्षित होवें ताकि यह पुष्टि हो सके कि गिर रहे संसाधनों को और गिरने से बजाया जा सके। यह मामला सिर्फ चीनी मिलों में परिवर्तन के लिए पूंजी के पैसे पुनःनिर्धारित करने या नए व्यवसायों को लेकर नहीं है। यह कर्मचारियों के विस्तृत पुनःप्रशिक्षण तथा योग्यता में निखार लाने और उन लोगों का ख्याल रखने की है जो व्यवस्थित परिवर्तन के कारण का शिकार हुए हैं। स्वास्थ्य की नीतियां एन सी डी जैसे स्वास्थ्य विषयों से अपने को ढाल नहीं सकी है जोकि इस वक्त फीजी में मृत्यु का खास कारण बनी हुई है। उच्च स्वास्थ्य आर्थिक नीतियां कायम करने के लिए सही कदम उठाए जाने की कमी वर्षों से समस्या बनी हुई है। हाऊज़िंग नीतियों के कारण कम खर्च वाले घर लोगों को प्रदान करने में असफलता मिली है और यही वजह है कि शहरों में जनाबादी तेज़ी से बढ़ रही है जिसके कारण झोपड़-पट्टियों में रहने वालों की संख्या बढ़ी है।

*नीतियां एक दूसरे से मिलती जुलती है, समय के साथ निर्भर तथा विश्वसनीय होनी चाहिए।*

नीतियां एक दूसरे से मिलती-जुलती होनी चाहिए ताकि दोनों में आपसी मज़बूती हो और ऐसा होने से एक-दूसरे में और असरकारिता को सहयोग मिलेगा। नीतियां इस हद तक मेलजोल रखने वाली न हों कि वे एक दूसरे से "लड़ाई" करें

और एक-दूसरे की असरकारिता को बाधा पहुंचाए। नीतियां जो एक-दूसरे से मेल न खाती हों सम्भवतः ठीक से ठीक सिर्फ आंशिक रूप से उदेश्यों में सफलता प्राप्त करती हैं या कुछ संदर्भ में कुछ भी हासिल नहीं होता।

समय के साथ-साथ नीतियों को मेल खाने वाली होनी चाहिए। नीतियों की असरकारिता पर असर तब पड़ेगा जब समय-समय पर नीतियों के उद्देश्य में परिवर्तन तथा लगातार कांट-छांट किया जाता रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि नई नीतियां लागू करने तथा उसे पूर्ण रूप से असर में आने के बीच समय का लम्बा फासला होता है। आर्थिक नीतियां, उदाहरण के तौर पर सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था में तब तक एक सूद की दर में हुए परिवर्तन का सम्पूर्ण असर नहीं दिखता जब तक दो या तीन वर्ष नहीं हो जाता। शिक्षा और स्वास्थ्य नीतियों में हुए परिवर्तन के बीच के समय का असर इससे भी और लम्बा हो सकता है। बदलती हुई नीतियों को उसके पूर्ण असर को पहले से देखना न सिर्फ बेकार होगा बल्कि बर्बादी तथा उत्पादकता के खिलाफ होगा।

और अंत में नीतियां विश्वसनीय होनी चाहिए। इसके लागू होने से लोगों में विश्वास पैदा होनी चाहिए कि हां, ये नीतियां असरकारक होंगी तथा इससे बदलाव आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकांश नीतियों की असरकारिता बदलते हुए व्यवहारों पर निर्भर है और ये व्यवहार नहीं बदलेंगे अगर लोगों में यह आम विश्वास होगा कि ये नीतियां बेअसरकारक हैं। नीतियों की विश्वसनीयता पाने के लिए सरकार को किए जाने वाले अपने वादों के प्रति और सावधान होना पड़ेगा कि वे क्या प्रदान कर सकती है जैसे कि उसे वही करनी चाहिए जो वह वादा करती है।

**"डिपेन्डेन्सी सिन्ड्रोम" यानी दूसरों पर निर्भर होने की धारणा खासकर आदिवासी फीजियन समुदायों के बीच।**

यह सवाल है कि क्या आदिवासी फीजियन समुदाय के हित और विकास के लिए जो संस्थाएं बनी हैं, उनके काम करने के ढंग तथा व्यवस्था का संचालन उपनिवेषिक काल से अच्छे रहे हैं। क्या यह सही है कि "दूसरों पर निर्भर होने" की धारणा इनमें प्रचलित हैं जैसे कि "सब कुछ सरकार करेगी"। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या यह है कि सरकारी ढांचे, परम्परा तथा राष्ट्रीय तौर पर सुरक्षा

प्रदान करने वाली एजेन्सियों की बनावट का यह परिणाम है? क्या इन ढांचों में परिवर्तन से निर्णय लेने वाली प्रक्रिया पारदर्शित हो सकती है और निर्णय लेने वाले अपने समुदायों के प्रति और उत्तरदायित्व हो सकते हैं जिसके कारण दूसरों पर निर्भर होने वाले व्यवहार का प्रचलन कम हो सके? क्या इससे नीचले स्तर के आदिवासी फीजियन लोगों की सामाजिक व्यवस्था से सहयोग मिलेगा जिससे समुदायों से और भी ज़्यादा योगदान प्राप्त हो सकेगा?

**समाज के हर वर्ग तथा स्तर पर अप्रशिक्षित नेतागिरी।**

नेताओं को अपनी ज़िम्मेदारियों को भली-भांति सम्भालने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। नेता चाहे राजनीतिक हो, सार्वजनिक सेक्टर के हो, प्रायवट सेक्टर के हो या नागरिक समाज के हो, सभी परिस्थितियों में उन्हें कम से कम तीन अलग-अलग पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले उन्हें यह जानना ज़रूरी है कि उनकी संस्था के समक्ष ऐसे क्या विषय हैं जिनका सामना करना है (जैसे कि योजना तथा नीतियां जो उनके समक्ष हों)। दूसरा, उन्हें संचालन सम्बन्धि विषयों (उदाहरण के तौर पर आमदनी/पैसा उगाहने, असरकारक संसाधन प्रदान करना तथा मानव संसाधन विषय) पर ध्यान देना। उन्हें यह जानना है कि एक नेता के रूप में उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए जिसमें दूसरों के आगे बढ़ने के मौकों के लिए समय और स्थान होना चाहिए, अपने विश्वासों और मूल्यों को बताने "प्रथम भूमिका" में शिक्षित होना चाहिए। नेताओं में समाजों के बीच आपसी धार्मिक तथा सांस्कृतिक समझबूझ, एकता, शांति तथा अमचैन को बढ़ावा देने के साथ-साथ आपसी मेलमिलाप को बढ़ावा देते हुए नेतागिरी करनी चाहिए तथा उन्हें दूसरों के लिए उदाहरण बनना चाहिए। यह एक ऐसा ज्ञान है जो आसानी से नेताओं में देखने को नहीं मिलता है। यह जानना ज़रूरी है कि किसी समाज के हर स्तर पर नेतागिरी के मौके उपलब्ध हैं अगर इसे ज़्यादा से ज़्यादा असर में लाने की ओर कदम लिया जाए।

क्या देश को नेतागिरी वाली ट्रेनिंग उपलब्ध करने की और ज़रूरत है? और क्या इस तरह की ट्रेनिंग प्रायवट सेक्टर तथा नागरिक समाज को देना ज़रूरी है?

नेतागिरी की भूमिका समाज के हर स्तर पर किस तरह से लेना ज़रूरी है ताकि फीजी के भविष्य का निर्माण प्रभावशाली और असरकारक ढंग से हो सके। उदाहरण के तौर पर, स्थानीय सरकारी स्तर पर किस तरह की भूमिका निभानी चाहिए?

देश की सामंतीय नेतागिरी और ठोस की जा सकती है ताकि उसे और प्रयोगिक तथा समाजों के प्रति सम्बद्ध किया जा सके? ग्रेट काउन्सिल ओफ चीफ्स क्या लाभदायक भूमिका निभा सकती हैं?

## घटिया संचालन

फीजी में घटिया कार्यक्षमता के लिए कुछ हद तक घटिया संचालन को दोष दिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर चीनी व्यवसाय में बिना जला गन्ना को मिल तक समय पर पहुंचाने वाली समस्या एक संचालन विषय है। इसी प्रकार मुख्य टूरिस्ट होटलों में सामान्य तौर पर शाकभाजी पहुंचाने की पूर्व व्यवस्थाओं के समक्ष भी समस्याएं पैदा हुईं जिसके कारण लगातार उच्च स्तर के उत्पादन की सप्लाई सामान्य तौर पर नहीं हो सकी। यह भी संचालन की एक समस्या है। सिर्फ यही उदाहरण नहीं हैं बल्कि दो और भी उदाहरण हैं जहां संचालन क्षमता में कमी के कारण मौके संकुचित हुए हैं। क्या फीजी भर में पब्लिक, प्रायवट और एन जी ओ सेक्टरों में संचालन स्तर को और प्रतियोगी बनाने के लिए एक सुव्यवस्थित अभियान होना चाहिए?

## निष्कर्ष

ऊपर दिए गए सूची में जो विषय का उल्लेख किया गया है, उसी में से अधिकांश महत्वपूर्ण तथ्य ही देश के सम्पूर्ण सरकारी संचालन, सामाजिक तथा आर्थिक विकास में समस्याएं पैदा करती हैं। कई तरीके से तथा कुछ ही भिन्नताओं के साथ ये समस्याएं देश के सभी सेक्टरों तथा सरकारी संचालन जैसे पब्लिक सेक्टर, प्रायवट सेक्टर और नागरिक समाज पर छाई हुई है।

एन टी टी द्वारा स्थापित किए जाने वाले कार्यकारणी दल, एन टी टी तथा नेशनल काउन्सिल के लिए एक मुख्य सवाल यह है कि क्या इसी तरह के कई और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें इस सूची में शामिल करना है?

दूसरा, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यही मुख्य कारण हैं जो फीजी के घटिया संचालन को समझाते हैं तो यह अच्छा होगा कि प्रत्येक के साथ सीधे रूप से उस हद तक पेश आया जाए जो कि सम्भव है न कि अप्रत्यक्ष रूप से उनपर निर्भर रहा जाए या दूसरा कि समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्तिगत सेक्टरों से कहा जाए जो यह कहेंगे कि सरकार की लगातार अनुपयुक्त गतिविधियों, असामान्य नीतियों, नेतागिरी की कमी की योग्यता या गलत संचालन के कारण ऐसा हुआ है। दूसरा यह है कि ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि इन में से कौन सा विषय राष्ट्रीय स्तर पर उदाहरण के तौर पर सरकार संचालन में सुधार, सरकार की भूमिका का पुनःमुल्यांकन, "डिपेन्डेन्सी सिन्ड्रोम", तथा सरकार के बीच कार्य संचालन लागू करने के तरीकों से होता है जिससे प्रतियोगी, स्थिर, नीतियों की विश्वसनीयता बनाए रखते हुए संचालन तथा नेतागिरी में प्रशिक्षण के और मौके प्रदान प्राप्त हो सके।

# भाग 3

## आगामी कदम (या बहस/विचार-विमर्श की सुव्यवस्था)

अगली ज़िम्मेदारी होगी इन मुख्य तथ्यों के असरों का पता लगाना -कि इन तथ्यों को कैसे और किन तरीकों से आर्थिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेक्टरों से खत्म या कम किया जा सकता है। सुविधा के तौर पर इन्हें तीन विस्तृत वर्ग में रखा गया है जो ऐसे हैं, (ए) अच्छी सरकार, (बी) अर्थ व्यवस्था को बढ़ावा और (सी) सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान तथा राष्ट्रीय निर्माण।

इस तरह से कार्य बांटने से कुछ व्यवहारिक समस्याएं पैदा होती हैः वास्तविक दुनिया में सब कुछ एक दूसरे से सम्बद्ध है। पहला, कि कुछ ऐसे विषय हैं जो सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर इनमें शामिल हैं मानवाधिकार; लिंग भेद; जातिए सम्बन्ध; नेतागिरी; अच्छे संचालन; सरकार की भूमिका; आदिवासी फीजियन शासन; तथा सार्वजनिक सेवा में असरकारिता और व्यवस्था। इनमें से प्रत्येक को आसानी से सभी के कार्य के एक भाग के रूप में ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है। दूसरा, उत्पादन के क्षेत्र में कम मौके की प्राप्ति- ज़मीन, मज़दूर तथा पैसा- ये तीन इन क्षेत्रों में बढ़ने के सबसे मुख्य बाधक रहे हैं, लेकिन इन सब पर और भी सुविधाजनक रूप से एक अकेली नेशनल टास्क टीम में विचार विमर्श किया जा सकता है।

इन एक दूसरे से जुड़ी समस्याओं और/या एक दूसरे से मेल खाते हुए विषयों के साथ पेश आने के लिए कुछ आर्बिट्री निर्णय लेने की ज़रूरत है। जैसा कि प्रस्ताव है, उदाहरण के तौर पर कि आदिवासी फीजियन संस्थाओं से सम्बन्धित सभी विषयों पर सम्भवतः एक कार्यकारणी दल द्वारा ध्यान दिया जाएगा जो प्राययोरटि टोपिक 2 पर ध्यान देती है; सार्वजनिक सेवा वाला विषय कार्यकारणी दल को मिला है जो प्राययोरटि टोपिक 3 पर ध्यान दे रही है; ज़मीन का विषय उस कार्यकारणी दल को मिला है जो प्रायोरटि टोपिक 6 को मिला है; तथा मानवाधिकार और लिंग समानता वाला विषय सम्भवतः प्रायोरटि टोपिक 9 से जूझने वाले कार्यकारणी दल को मिला है।

अगर इन विषयों का वर्गीकरण असन्तोषजनक व्यवहारिक रूप देता है तो शायद यह ज़रूरी होगा कि इन व्यवस्थाओं को फिर से जोड़ा जाए, उदाहरण के तौर पर नेशनल टास्क टीम या वोर्किंग ग्रुप्स की संयुक्त सभा किसी खास विषय पर बुलाया जाए जिसमें एक विस्तृत

विचार विमर्श की आवश्यता होगी।

प्रत्येक नेशनल टास्क टीम में जिन मुख्य विषयों पर विचार विमर्श होंगे, वे निम्नलिखित हैं।

**नेशनल टास्क टीम 1: अच्छे शासन**

फीजी में अच्छे शासन में बाधा डालने वाले मुख्य विषयों पर टास्क टीम 1 ध्यान देगी। ये शासन मुख्य संस्थाओं जैसे, सरकार, संसद तथा न्यायालय हैं जो देश में कानून, प्रशासन जैसे विषयों को तैयार करने में उलझी हुई होती है और जिसके मार्फत फीजी का संचालन होता है।

सुविधा के तौर पर टास्क टीम 1 द्वारा जो कार्य किया जाएगा, उन्हें निम्नलिखित चार मुख्य क्षेत्रों या शीर्षकों में बांटा गया है:

- **प्रायोरटि टोपिक 1: प्रजातांत्रिक शासन के लिए ढांचा, जिसमें संवैधानिक और कानूनी विषय शामिल है;**

सरकारी रूपरेखा खासरूप से संविधान, चुनाव प्रणाली तथा बहु-पार्टी ताकत वाली व्यवस्था पर ध्यान देती है। इससे मुख्य सवाल उठता है कि क्या वर्तमान संवैधानिक रूपरेखा फीजी में अच्छे शासन और प्रजातंत्र के लिए बाधक है या उसे और बढ़ावा देती है। फीजी में लगातार राजनीतिक अस्थिरता के लिए अच्छे शासन की असफलता ज़िम्मेदार रही है। देश के निर्माण के रास्ते में जातिए आधार की नीतियां और राजनीति ने विभाजन करते हुए बाधक बने हैं।

- **प्रायोरटि टोपिक 2: नेतागिरी वाले विषय तथा संस्थापित ढांचा**

नेतागिरी तथा संस्थापित विषय इस तरीके से देखा जाता है कि देश में सार्वजनिक प्रशासन का संचालन कैसे होता है। सार्वजनिक दफ्तरों में संचालन का स्तर चिन्ता का एक विषय है और यह चिन्ता कुछ मुख्य उच्च संस्थाएं जो आदिवासी फीजियन दिलचस्पियों का समर्थन करती हैं, पर भी की जा रही हैं।

- **प्राययोरटि टोपिक 3: पब्लिक सेर्विस रिफोर्म**

पब्लिक सेर्विस में संचालन के सुधार के अगले कदम क्या होंगे, इससे पब्लिक सेर्विस रिफोर्म सम्बन्ध रखता है और सरकार जिसमें गव़मेंट बिज़नेस एण्टरप्राइसस शामिल है, उसके भावी व्यवसायिक कार्यों को देखता है।

- **प्रायोरटि टोपिक 4: राष्ट्रीय निर्माण में फीजी सुरक्षा दलों की भूमिका**

फीजी की राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरतों के भविष्य पर ख़ासतौर से राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बद्ध है जिसका काम है फीजी मिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्स तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाओं की भूमिकाओं को स्पष्ट करना। ख़ासतौर से ये लगातार "कू कल्चर" को ख़त्म करने की ज़रूरतों पर लिए गए कदम के लिए ज़िम्मेदार है।

**नेशनल टास्क टीम 2: अर्थ व्यवस्था को बढ़ावा**

टास्क टीम 2 ख़ासतौर से उन समस्याओं का पता लगाएगा जिनके कारण से फीजी की अर्थ व्यवस्था धीमी है, दर ऊपर करने के क्या तरीके हैं, नौकरी निर्माण में वृद्धि तथा आर्थिक मौकों में समानता में कैसे सुधार लाया जाए। एन टी टी 2 दल को राष्ट्रीय काउन्सिल ने जो काम दिए हैं, उन्हें नीचे दिए गए चार मुख्य शीर्षक में दिए जा रहे हैं:

- **प्रायोरटि टोपिक 5: सरकार, प्रयवट सेक्टर तथा नागरिक समाज की भूमिकाओं का स्पष्टीकरण**
  - प्रत्येक सेवा प्रदान करने की साझेदारी में किस तरह से असरकारक और अच्छे ढंग से एक दूसरे के साथ काम किया जा सकता है, इन विषयों पर सरकार, प्रायवट सेक्टर तथा सीविल सोसाइटि की भूमिकाओं को स्पष्ट करना।
  - प्रायवट सेक्टर के निर्णय लेने वाली प्रकिया में सरकार के प्रभुत्व को कम करना
- **प्रायोरटि टोपिक 6: ग्रोथ, इक्विटी एण्ड सस्टेन्बिलिटी**
  - बड़ी आर्थिक नीतियों की व्यवस्था का पुनःविचार करना।
  - परिवर्तनशील बाहरी वातावरण के साथ व्यवस्थित रूप से ढालने की क्षमता में तेज़ी लाने के सुधार के तरीकों पर विचार करना।
  - सामाजिक न्याय कार्यक्रमों के असरकारिता का पुनःविचार करना (जैसे कि अफेर्मेटिव् एक्शन प्रोग्रेम) और आर्थिक मौके को प्राप्त करने में सामनता लाने वाले सुधार के प्रस्ताव पर विचार करना।
  - ऐसी प्रकिया का पुनःविचार करना जिससे यह पुष्टि हो सके कि पर्याप्त मात्रा में तथा समय के साथ लीस वाली ज़मीन, उत्पादनशील सेक्टरों को घरों के लिए ज़मीन ख़ासकर शहरी इलाकों में प्रदान की जा सके।

- वातावरण संचालन व्यवस्थाओं के असरकारिता और पूर्णता का पुनःविचार।

- **प्रायोरटि टोपिक 7: फाइनेन्शियल सेर्विस सेक्टरों का विकास**
  - उन तरीकों का पता लगाना जिनसे आर्थिक बाज़ार की जटिलता में वृद्धि और गहराई प्राप्त हो सके ताकि (खासकर ग्रामीण इलाकों और बाहरी द्वीपों) को भी विस्तृत तथा असरकारक सेवा मिल सके।
  - पैसों के नियंत्रण की ज़रूरतों पर पुनःविचार।
  - एफ एन पी एफ पूंजी के संचालन के लिए वर्तमान व्यवस्थाओं को लम्बे समय तक बरकरार रखने पर पुनःविचार।
  - सुपरएनुएशन फण्ड्स के संचालन को और प्रतियोगी तथा मुक्त करने के तरीकों का पता लगाना।

- **प्रायोरटि टोपिक 8: संसाधनयुक्त सेक्टरों का विकास**
  - उन तत्थों (ज़मीन से परे) जो संसाधन के विकास में धीमापन (कृषि, फिशरीज़, फोरेस्ट्री और मिनरल्स) लाते हैं तथा सेक्टरों के संचालन में और सुधार तथा मुनाफे के लिए सिफारिश करना, शामिल हैः
    - चीनी व्यवसाय का पुनःविकास;
    - कृषि आधारित प्रक्रिया;
    - सप्लाई करने वाले विषय जैसे खासरूप से खेती वाले उत्पादनों को बाज़ार ले जाने वाले यातायात जैसे विषयों के अलावा कृषि सेक्टर में और ज़्यादा मूल्य जोड़ने वाले तरीकों का पता लगाना।

**नेशनल टास्क टीम 3: सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय निर्माण**

वर्तमान में फीजी के नागरिक अपनी पहचान राष्ट्रीयता के द्वारा नहीं बल्कि समुदायों के द्वारा देते हैं। राष्ट्रीय निर्माण और मेलमिलाप में यह मुख्य बाधा है। मानवाधिकार के उल्लंघन के कई गम्भीर नमूने देखने को मिले खासकर महिलाओं, विक्लांग लोगों तथा अल्पसंख्यक जातिए दलों के अधिकारों के साथ ऐसा हुआ है। जनाबादी की एक तिहाई हिस्सा आवश्यक ज़रूरतों को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। जबकि गरीबी के अर्थ तथा उसकी सीमा बहस वाला एक कारण बना हुआ है, वहीं अधिकांश लोग गरीबी की सीमा का हद पार कर चुके हैं। इन लोगों को मदद करने के लिए सामाजिक न्याय योजना का विकास करना ज़रूरी है जिसमें मज़दूर बाज़ार के संचालन में सुधार से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, हाऊज़िंग और लोगों के अधिकारों को लेकर खर्चे वाले कार्यक्रमों

को लागू करना है। एन टी टी 3 तीनों कार्यकारणी दलों को इसमें उल्झाएगा। नीचे दिए गए तीन प्राथमिकता वाले शीर्षकों में इन विषयों पर विचार सारांश में किया गया है।

- **प्रायोरटि टोपिक 9: गरीबी, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार**
  - गरीबों को सहायता पहुंचाने के लिए नीतियों और योजनाओं का पता लगाना;
  - गरीबी कम करने के कदमों के संचालन और कार्यक्षमता का पता लगाना;
  - सामाजिक न्याय कार्यक्रम के असरकारिता का पुन:विचार करना और यह देखना कि वे संविधान की व्यवस्थाओं से मेल खाते हैं;
  - मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उन्हें सुरक्षित रखने वाले वर्तमान मानवाधिकारों के कानूनों के असरकारिता का पुन:विचार करना; और - सम्पूर्ण जनता तथा पब्लिक सेक्टर के बीच मानवाधिकारों की परम्परा को किस रूप से फीजी बढ़ावा दे सकता है, इसका मूल्यांकन करना।

    (नोट: मानवाधिकार कमीशन को मज़बूत करने सम्बंधी विषयों पर प्रायोरटि टोपिक 2 के तहत विचार-विमर्श किया जाएगा)।

- **प्रायोरटि टोपिक 10: शिक्षा, स्वास्थ्य और हाऊज़िंग की मूल ज़रूरतों की पूर्ति**
  - फीजी की शिक्षा प्रणाली पर पुन:विचार;
  - स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में सुधार सम्बंधी नीतियों और उस के आर्थिक विकल्पों को बनाना; और
  - झोपड़-पट्टियों की संख्या कम करने के तरीकों का पता लगाना और आवश्यक मूल इन्फस्ट्रक्चर तथा कम दाम वाले और घर प्रदान करना।

- **प्रायोरटि टोपिक 11: राष्ट्रीय निर्माण में धर्म तथा संस्कृति की भूमिका तथा राष्ट्रीय पहचान**
  - देश के लिए मेलमिलाप और पुन:निर्माण प्रक्रिया में फीजी के लिए राष्ट्रीय पहचान के महत्व का मूल्यांकन करना;
  - विकासशील आधुनिक अर्थ व्यवस्था के समक्ष सांस्कृतिक रद्दोबदल के संचालन और प्रक्रिया में विचार विमर्श करना और पता लगाना; और

- देश के विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच समझबूझ तथा सहकारिता को बढ़ावा देने वाली कार्यवाहियों और नीतियों को बनाने की सिफारिश करना।

**काम सुव्यवस्था**

दिए गए काम करते वक्त तीनों नेशनल टास्क टीमों को ध्यान में यह रखना होगा कि जो अध्ययन पहले से समाप्त किए जा चुके हैं, उनमें भावी छानबीन उन्हीं क्षेत्रों में करने की ज़रूरत होगी जहां यह देखा जाएगा कि काम को और संतोषजनक ढंग से करने की ज़रूरत है।एन टी टी दी गई अपनी ज़िम्मेदारियों को प्राथमिकता देने पर विचार करेगा और ऐसा करते हुए उसे उन्हीं सिफारिशों की कार्यवाहियों को लागू करने के लिए एक समय-सूची की रूपरेखा तैयार करनी होगी ताकि यह पुष्टि हो सके कि उनका काम सही ढंग से हो रहा है। तकनीकी और सहयोगी सेक्रेटेरियट (टी ए एस एस) के मुखिया के साथ अपने विचारों को व्यक्त करते हुए प्रत्येक एन टी टी, साहित्यिक पुनःविचार की तैयारी, विषयों को जारी तथा विचार विमर्श वाले कागज़ात (आई डी पीस) की मांग कर सकता है।

प्रत्येक एन टी टी कार्यकारणी दलों (डब्लू जीस) की स्थापना कर सकती है अगर वो ऐसा करना ज़रूरी और उपयुक्त समझती है ताकि प्रायोरटि टोपिक्स के कार्य अच्छी तरह हो सके। प्रत्येक कार्यकारणी दल को एन टी टी को एक निर्धारित समय-सीमा के बीच रिपोर्ट करनी होगी।

# Annex 1: Key Economic and Social Indicators

| | (70-79) | (80-89) | 90-99) | (00-06) |
|---|---|---|---|---|
| **Economy** | **1970s** | **1980s** | **1990s** | **2000s** |
| Real GDP growth rate | 5.0 | 1.9 | 3.0 | 2.0 |
| GDP per Capita F$ | 975.00 | 1,857.00 | 3,327.00 | 5,613.84 |
| Inflation Rate avg | 9.1 | 7.5 | 4.2 | 2.6 |
| Exports as % of GDP | 28.3 | 29.3 | 37.5 | 33.2 |
| Imports as % of GDP | 51.0 | 46.1 | 53.9 | 61.7 |
| Investment as % of GDP | 21.8 | 18.8 | 14.6 | 15.1 |
| Visitor Arrivals (average) | 167,143 | 201,882 | 322,201 | 447,332 |
| **Government** | | | | |
| Debt as % of GDP | 24.2 | 40.7 | 43.9 | 55.5 |
| **Demography** | **1976** | **1986** | **1996** | **2006** |
| Population | 588,068 | 715,375 | 775,077 | 827,900 |
| - Fijian | 259,932 | 329,305 | 393,575 | 473,983 |
| - Indian | 292,896 | 348,704 | 338,818 | 311,591 |
| - Others | 35,240 | 37,366 | 42,684 | 42,326 |
| | | | | |
| - Rural | 369,573 | 436,239 | 415,582 | 406,814 |
| - Urban | 218,495 | 272,734 | 359,495 | 421,086 |
| | | | | |
| Population density *(persons per sq. km)* | --- | --- | 42 | 46 |
| Urban population *% of total population* | 37.15 | 38.12 | 46.38 | 50.86 |
| **Health** | | | | |
| Life Expectancy | 61.6 | 66.9 | 66.6 | 68.5 (2005) |
| Total Fertility Rate | 3.5 | 5.1 | 3.3 | 2.7 (2000) |
| Infant Mortality Rate *per 1000 live births* | --- | 16.8 (1990) | 14.7 (1995) | 19.5 (2006) |
| Maternal Mortality Rate *per 100,000 live births* | --- | 41.1 (1990) | 60.4 (1995) | 32.6 (2006) |
| **Education** | | | | |
| Net Primary Enrolment ratio | --- | --- | 96.7 (1999) | 92.9 (2003) |
| Teacher Pupil ratio | | | | |
| - Primary | --- | --- | 1:29 (2000) | 1.28 (2007) |
| - Secondary | --- | --- | 1:19 (2000) | 1:19 (2007) |
| **Labour Force** | | | | |
| Unemployment rate | 6.7 | 7.5 | 5.8 | 4.6 (2004-5) |
| **Crime** | **2002** | **2003** | **2004** | **2005** |
| Serious Crime Cases | 4664 | 4467 | 4406 | 4608 |